व्यापार करने वाले निगम

475. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे कई निगमों द्वारा व्यापार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा देश में कितने रुपये का कारोबार किया गया तथा उन्होंने कितने रुपये का आयात और निर्यात किया; और

(घ) इनमें से किस-किस निगम को कितना लाभ/कितनी हानि हुई, कितने का माल बर्बाद हुआ, कितने का माल चोरी हो गया, कितने रुपये के लिए बीमा कम्पनियों में दावे किये गये तथा इसी अवधि के दौरान बीमा कम्पनियों ने तकनीकी कारणों से कितने रुपये के दावों को अस्वीकृत कर दिया ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ट्रैक्टर और पावर टिलर

476. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा. बापू कालदाते :

क्या उद्योग मंत्री 17 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2033 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न तो सरकार के पास और न ही ट्रैक्टर कम्पनियों के पास कोई ऐसा सस्ता ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए जिसे सीमान्त, छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों द्वारा प्रयुक्त किया जा सके, कोई योजना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष पावर-टिलर निर्माताओं, उद्योग मंत्रालय और संसद सदस्यों के बीच हुई एक अनौपचारिक बैठक में मंत्रालय द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि जब तक सरकार पावर-टिलर निर्माताओं को अनुदान नहीं दिया जाता है तब तक यह यंत्र किसानों की पहुंच से बाहर होगा; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत तक बड़े किसान ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं जबकि छोटे किसान पिछड़े ही रहते हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) ट्रैक्टरों, शक्तिचालित हलों तथा विभिन्न आकारों की कृषि मशीनों को शामिल करने के लिए वर्तमान निर्माताओं को अपने उत्पादों की श्रेणी में विविधता लाने के लिए पूरी ढील दी गई है । इसके अतिरिक्त किसानों के लाभ के लिए 25 पी०टी० ओ० एच०पी० तक के ट्रैक्टरों तथा शक्तिचालित हलों पर उत्पादनकर में छूट दी गई है । उक्त बैठक में राज सहायता का प्रश्न सामने आया । कुछ राज्यशक्ति चालित हलों की खरीद के लिए राज-सहायता देते हैं । ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है।

बरियारपुर में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

477. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा० बापूकालदाते :

क्या संचार मंत्री 3 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 643 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरियारपुर मुंगेर में टेलीफोन नं० 25 और 30 बराबर खराब रहते हैं और अधिकांशत: रेल-गाड़ियों के समय के बारे में कभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है; और

(ख) बरियारपुर, मुंगेर और जमालपुर में, पृथक्-पृथक् रूप से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा के क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं । जब कभी दोषों के बारे में रिपोर्ट मिलती है उन्हें तुरंत दूर कर दिया जाता है।

(ख) स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) इस समय बारियारपुर में एस० टी० डी० सुविधा व्यवहार्य नहीं है ।

(2) मुंगेर के लिए एस० टी० डी० सुविधा जुलाई, 1986 तक उपलब्ध होने की संभावना है ।

(3) जबलपुर के लिए एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने पर विचार किया जा रहा है ।

हाइड्रो-कार्बन की खोज में विदेशों का सहयोग

478. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा० बापू कालदाते :

क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कार्य का ब्यौरा क्या है जिसमें सोवियत रूस ने हाइड्रोकार्बन का पता लगाने में अपना सहयोग दिया है तथा इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और क्या किसी अन्य देश ने भी इस संबंध में अपना सहयोग दिया है;

(ख) तटीय क्षेत्र के अनुमानित 100 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा अपतटीय क्षेत्र के प्रति वर्ष 379 बिलियन क्यूबिक मीटर में से अब तक प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जा रही है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या पूरे देश का सर्वेक्षण-कार्य पूरा कर लिया गया है या क्या कोई भाग अभी भी बचा हुआ है तथा उन स्थानों के नाम क्या है जहां प्राकृतिक गैस के पता चलने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) भारत में भूकंपीय आंकड़ों के अधिग्रहण भूगर्भीय, भूभौतिकीय तथा खनन संबंधी आंकड़ों के संसाधन तथा उनकी व्याख्या, भंडारण की मूल्यांकन और उनका विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों जैसे हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के विभिन्न पहलुओं के लिए सोवियत सहायता प्राप्त की गई है । हाल ही में बार्ध बेसिन तथा बाकेर तटवर्ती बेसिनों के आपस में सहमत क्षेत्रों में तेल और गैस के लिए गहन तथा एकीकृत अन्वेषण करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया गया है । आशा है कि परियोजना लागत का 70 प्रतिशत भाग सोवियत सहायता से पूरा किया जायेगा ।

कैम्बे, अपर असम, हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, राजस्थान, बंगाल के अपतटीय बेसिनों जैसे देश के विभिन्न तलछटी बेसिनों में सोवियत सहायता से विभिन्न प्रारूपियों की गई थी । इनमें से कुछ बेसिनों में हाइड्रोकार्बनों के होने का पता लगा है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1961 में फ्रांस के आई०एफ०पी० के साथ राजस्थान के जैसलमेर शहर के पश्चिम में एक क्षेत्र में संयुक्त अन्वेषण के लिए सहयोग करार किया था जहां मनहेर टिब्बा गैस क्षेत्र मिले थे ।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान बंबई हाई अपतटीय क्षेत्र तथा गुजरात क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, उपभोग तथा जलाने के संबंध में स्थिति इस प्रकार है—

क्षेत्र	प्रति वर्ष उत्पादन	मिलियन घनमी० प्राकृतिक गैस	
		उपयोग की गई	जलाई गई
बम्बई हाई	4971	2868	2103
गुजरात क्षेत्र	883	776	107